धन तथा सरकार से प्राप्त सहायता को ध्यान में रखकर अपने विकास परियोजनाओं को योजनाएं बनाता है।

(ङ) जी नहीं।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत रोजगार आश्वासन योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना

2846. **श्री जनार्दन यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय योजना 1995-96 के अन्तर्गत बनाई गई रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को बिहार में किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है और इस संबंध में खंड-वार जुटाये गये रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस), केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में ई ए एस दिशानिर्देशों के अनुरूप देश के 3198 ब्लाकों में कार्यान्वित की गई है। ई ए एस के लिए कार्य योजना जिला कलेक्टर/जिला उपायुक्त द्वारा तैयार की जाती है, जो इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी है।

(ख) केन्द्र एवं राज्य द्वारा जारी निधियों, किया गया व्यय, तथा सृजित श्रम दिवस अनुपत्र में दिए गए हैं। **(देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 67]**

(ग) ई ए एस दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना बिहार के 447 ब्लाकों में कार्यान्वित की गई है। रोजगार सृजन का ब्लाक-वार ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता।

Statutory Auditor's report on Super Bazar

2847. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the statutory auditors in the Super Bazar have rendered any report on (i) non-recoverable amounts outstanding against the borrowing departments, (ii) damaged goods for non saleable goods and (iii) amounts outstanding against the employees of super bazar on account of shortages/pilferages etc.;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(c) how much money is locked up with the borrowers, with the employees and in the damaged goods/unsaleable goods and what steps have been taken by the super bazar to realise the outstanding amounts and to get rid off the damaged/unsaleable goods so as to know the true state of financial status of the bazar?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) The Statutory Auditors of the Super Bazar have submitted their report for the year 1994-95, which is yet to be accepted by the General Body of the Super Bazar. The Auditors have, inter alia, indicated that a part of the sundry debtors against credit sale is doubtful. The have, however, not said that it is non-recoverable.

(b) and (c) According to the Audit Report, details in this regard as on 31.3.95 are as follows:—

		(Rs. in lakhs)
(i)	Outstanding borrowing	912.29
(ii)	Damaged stock	1.71
(iii)	Old/slow moving stock	1.86
(iv)	Shortage/pilferage by employees during the year 1994-95	31.12

It has also been reported by the Super Bazar, that they are making efforts to recover credit sales outstanding, taking steps for disposal of damaged/slow moving stocks and conducting enquiries for recovery of shortages from the concerned employees.